

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमति क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 475]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 27 अगस्त 2021 — भाद्रपद 5, शक 1943

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 26 अगस्त 2021

अधिसूचना

क्रमांक एफ 4-6/2020/एक/6.— राज्य शासन, एतद् द्वारा गौरेला—पेण्ड्रा—मरवाही, मुंगेली, बिलासपुर एवं कोरबा जिलों की सीमा अन्तर्गत बहने वाली अरपा नदी के अन्तर्गत आने वाले भू-भाग के समग्र विकास हेतु “अरपा बेसिन विकास प्राधिकरण” का गठन करता है। प्राधिकरण के गठन एवं कार्य निम्नानुसार होंगे :—

1. प्राधिकरण के उद्देश्य :—

- (1) अरपा नदी के जलग्रहण क्षेत्र के विकास का उपाय करना, जिससे अरपा नदी में बारह माह पानी रहे। इसमें नरवा कार्यक्रम के अन्तर्गत वैज्ञानिक आधार पर विभिन्न आवश्यक संरचनाओं के निर्माण हेतु उपाय करना।
- (2) अरपा नदी के जलग्रहण क्षेत्र में निर्मित समस्त सिंचाई परियोजनाओं का पूरी क्षमता से सिंचाई हेतु संधारण के उपाय सुझाना।
- (3) अरपा नदी के जलग्रहण क्षेत्र में निर्माणाधीन समस्त योजनाओं को द्रुत गति से पूर्ण करने के उपाय करना।
- (4) अरपा नदी के जलग्रहण क्षेत्र में प्रस्तावित योजनाओं का मास्टर प्लान के द्रुत गति से लागू करने हेतु उपाय करना।
- (5) अरपा नदी को प्रदूषण मुक्त रखने के लिए आवश्यक उपाय करना।
- (6) अरपा नदी एवं इसकी सहायक नदियों एवं नालों का उपचार करना तथा उनके किनारे सघन वृक्षारोपण हेतु उपाय करना।

2. प्राधिकरण का कार्यक्षेत्र :—

गौरेला—पेण्ड्रा—मरवाही, मुंगेली, बिलासपुर एवं कोरबा जिलों में अरपा नदी के किनारे स्थित क्षेत्र एवं नदी के जलग्रहण क्षेत्र में आने वाले समस्त ग्राम।

स. क्र.	जिले का नाम	विकासखण्ड का नाम
(1)	(2)	(3)
1	गौरेला—पेण्ड्रा—मरवाही	पेण्ड्रा, गौरेला
2	मुंगेली	लोरमी
3	बिलासपुर	कोटा, तखतपुर, बिल्हा, मस्तूरी
4	कोरबा	पाली

3. प्राधिकरण के कार्य एवं शक्तियाँ :-

- (1) स्थानीय स्तर पर अरपा नदी के विकास की अल्पकालिक एवं दीर्घकालिक योजनाओं के निर्माण के लिये आवश्यक पहल करना तथा राज्य शासन द्वारा प्राधिकरण क्षेत्र में संचालित योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा और अनुश्रवण सुनिश्चित करना।
- (2) प्राधिकरण को योजनाओं के अनुकूलतम उपयोग के लिये संबंधित विभाग को दिशा-निर्देश/मार्गदर्शन देने का अधिकार होगा।
- (3) प्राधिकरण क्षेत्र के विकास के लिये आवश्यक प्रस्ताव तैयार कर राज्य शासन को प्रस्तुत करेगा।
- (4) प्राधिकरण को राज्य शासन द्वारा अरपा नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में सिंचाई सुविधाओं के विकास के लिये उपलब्ध करायी गयी राशि से क्षेत्रान्तर्गत नितान्त आवश्यक स्थानीय महत्व के छोटे-छोटे कार्यों को प्रस्तावित करने का अधिकार होगा।

प्राधिकरण को स्थानीय स्तर पर अन्य ऐसे समस्त विधिक कार्य संपादित करने की शक्ति होगी, जो प्राधिकरण के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु आवश्यक हो।

4. प्राधिकरण का गठन :-

अध्यक्ष	-	माननीय मुख्यमंत्रीजी
उपाध्यक्ष	-	शासन द्वारा नामांकित किया जावेगा।
सदस्य	-	शासन द्वारा क्षेत्रीय विधायक नामांकित किये जावेंगे।
सदस्य	-	शासन द्वारा क्षेत्रीय विधायक नामांकित किये जावेंगे।
सदस्य	-	शासन द्वारा क्षेत्रीय विधायक नामांकित किये जावेंगे।
सदस्य	-	शासन द्वारा नामांकित किया जावेगा।
सदस्य सह सचिव	-	प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग।

प्राधिकरण के पदाधिकारी के संबंध में निर्णय लेने हेतु माननीय मुख्यमंत्री जी अधिकृत रहेंगे। प्राधिकरण अपनी बैठकों में नियमित रूप से या विशेष रूप से प्राधिकरण क्षेत्र के किसी भी शासकीय अथवा अशासकीय व्यक्तियों को आमंत्रित कर सकेगा।

5. प्राधिकरण की बैठक :-

प्राधिकरण की बैठके प्रत्येक वर्ष में तीन बार होंगी। बैठक स्थल, दिन, समय एवं चर्चा के बिन्दुओं (एजेंडा) की संसूचना प्राधिकरण के समस्त सदस्यों को सदस्य सह सचिव द्वारा निर्धारित तिथि से कम से कम सात दिवस पूर्व दी जावेगी। बैठक में लिये गये निर्णयों/ संस्तुतियों से सभी संबंधितों को बैठक की कार्यवाही विवरण के माध्यम से अवगत कराया जावेगा।

6. प्राधिकरण के निर्णयों का क्रियान्वयन :-

प्राधिकरण के द्वारा लिये गये निर्णयों एवं स्वीकृतियों की संसूचना सदस्य सह सचिव के हस्ताक्षर से जारी की जावेगी।

7. प्राधिकरण की निधि :-

अरपा बेसिन विकास प्राधिकरण के संबंध में अलग से निधि का प्रावधान नहीं किया जावेगा। प्राधिकरण द्वारा विभागीय बजट प्रावधान के अन्तर्गत प्रस्तावित योजनाओं पर समीक्षा, सुझाव, विकास हेतु प्रस्ताव तथा क्षेत्र के मैदानी प्रतिवेदन से शासन को अवगत कराया जावेगा। प्राधिकरण के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्यों को मानदेय, आकस्मिक व्यय, दैनिक भत्ता इत्यादि हेतु विभागीय बजट में प्रावधान किया जावेगा। प्राधिकरण के निधि नियम निम्नानुसार है :-

7.1 संक्षिप्त नाम, प्रारंभ तथा विस्तार -

- (i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम “अरपा बेसिन विकास प्राधिकरण निधि नियम 2021” होगा।
- (ii) ये नियम छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।
- (iii) इसका विस्तार अरपा नदी के छत्तीसगढ़ राज्य के जलग्रहण क्षेत्र तक होगा।

निम्नलिखित ब्लाक एवं जिला का क्षेत्र अरपा नदी के जलग्रहण क्षेत्र के अन्तर्गत आता है। अतः अरपा बेसिन विकास प्राधिकरण के कार्य का विस्तार निम्नलिखित ब्लाक एवं जिलों में अरपा नदी के जलग्रहण क्षेत्र तक होगा –

स. क्र.	ब्लॉक का नाम	जिला
(1)	(2)	(3)
1.	पेण्ड्रा	गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही
2.	गौरेला	गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही
3.	लोरमी	मुंगेली
4.	कोटा	बिलासपुर
5.	तखतपुर	बिलासपुर
6.	बिल्हा	बिलासपुर
7.	मस्तूरी	बिलासपुर
8.	पाली	कोरबा

7.2 परिभाषाएँ –

इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो –

- (i) “प्राधिकरण” से अभिप्रेत राज्य सरकार द्वारा गठित किया गया “अरपा बेसिन विकास प्राधिकरण” है।
- (ii) “निधि” से अभिप्रेत है, प्राधिकरण को आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग के बजट से प्रतिवर्ष मांग संख्या 41 लेखा शीर्ष के अन्तर्गत विभिन्न जल संसाधन संरचनाओं/बाढ़ नियंत्रण/तट रक्षण कार्यों के लिए सर्वेक्षण, निर्माण आदि हेतु निधि उपलब्ध कराने तथा मांग संख्या 41 के अन्तर्गत नगरीय निकाय विभाग, पी.एच.ई.एवं वन विभाग के अन्तर्गत उपलब्ध कराई जाने वाली राशि जिससे प्राधिकरण अपने उद्देशयों की पूर्ति कर सके।

7.3 निर्णयों का क्रियान्वयन –

- (i) माननीय सदस्यों/क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों की मांग के अनुरूप क्रियान्वयन विभाग से प्राप्त प्रस्ताव अनुसार रूपये 2.00 करोड़ तक की प्रशासकीय स्वीकृति जारी करने का अधिकार प्राधिकरण को होगा। प्रशासकीय स्वीकृति जारी कर प्राधिकरण इसकी सूचना संबंधित क्रियान्वयन विभाग को जारी करेगा। रु. 2.00 करोड़ से ज्यादा के कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति प्राधिकरण की अनुशंसा से शासन द्वारा जारी की जाएगी। रु. 50.00 लाख तक की लागत के कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति प्राधिकरण की अनुशंसा पर संबंधित कलेक्टर द्वारा जारी की जाएगी।
- (ii) क्रियान्वयन किये जाने वाले समस्त कार्यों का लेखा का संधारण क्रियान्वयन विभाग द्वारा विभाग में लागू नियमों के अनुसार किया जाएगा।
- (iii) प्रशासकीय स्वीकृत कार्यों की तकनीकी स्वीकृति क्रियान्वयन विभाग में अद्यतन नियमों के अनुसार दी जाएगी।
- (iv) प्रशासकीय स्वीकृति के लिए प्रस्तुत प्रत्येक प्रस्ताव में यह बताना आवश्यक होगा कि प्रस्ताव अरपा नदी की किस सहायक नदी के किस नाले के जलग्रहण क्षेत्र में स्थित है।
- (v) रु. 50.00 लाख तक की प्रशासकीय स्वीकृति प्रस्ताव क्रियान्वयन विभाग के जिला स्तर अधिकारी द्वारा संबंधित कलेक्टर को प्रस्तुत किया जाएगा।
- (vi) रु. 50.00 लाख से अधिक एवं रु. 2.00 करोड़ तक के प्रशासकीय स्वीकृति प्रस्ताव क्रियान्वयन विभाग के विभागाध्यक्ष के माध्यम से प्राधिकरण को प्रस्तुत किया जाएगा।
- (vii) रु. 2.00 करोड़ से अधिक के प्रशासकीय स्वीकृति प्रस्ताव क्रियान्वयन विभाग के माध्यम से शासन को प्रस्तुत किये जायेंगे।
- (viii) प्रशासकीय स्वीकृति हेतु प्रत्येक कार्य (कार्यों के समूह) के लिए प्राधिकरण की अनुशंसा अनिवार्य होगी। यह अनुशंसा प्राधिकरण द्वारा संलग्न परिशिष्ट—“अ” में दी जाएगी।

7.4. प्राधिकरण के अन्तर्गत लिए जाने वाले कार्य –

अरपा बेसिन विकास प्राधिकरण के अन्तर्गत अरपा नदी के छत्तीसगढ़ राज्य के जलग्रहण क्षेत्र में निम्नलिखित कार्य किया जाना प्रस्तावित है:-

(i) जल संवर्धन के कार्य –

वैज्ञानिक आधार से अरपा नदी के जल ग्रहण क्षेत्र के नदी नालों में जल का संवर्धन करने का कार्य। इसमें बोल्डर चेकडेम, कंटूर बंडिंग, डबरी, तालाब, कुआं, बांध, डायवर्सन आदि का निर्माण कार्य की वृहद कार्ययोजना बनाना एवं तदानुसार निर्माण कार्य करना।

(ii) पीने के पानी की व्यवस्था –

अरपा नदी के जल ग्रहण क्षेत्र के अन्तर्गत पीने के पानी की समुचित व्यवस्था का कार्य। इसके अन्तर्गत जल आवर्धन योजना, ट्यूबवेल, बोर वेल, कुओं इत्यादि का निर्माण कार्य।

(iii) नदियों को प्रदूषण मुक्त रखने की व्यवस्था –

अरपा नदी के जल ग्रहण क्षेत्र की नदियों को प्रदूषण मुक्त रखने के लिए आवश्यकतानुसार सीवेज ट्रीटमेण्ट प्लांट, गंदे पानी निकासी की व्यवस्था इत्यादि का कार्य।

(iv) नदियों के कटाव की रोकथाम, तटरक्षण एवं बाढ़ नियंत्रण कार्य –

अरपा नदी के जल ग्रहण क्षेत्र के अन्तर्गत विभिन्न नदी नालों में तटरक्षण, कटाव रोकने का कार्य तथा बाढ़ नियंत्रण का कार्य।

(v) निर्माणाधीन सिंचाई योजनाओं का द्रुतगति से निर्माण –

अरपा नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में निर्माणाधीन सिंचाई योजनाओं को द्रुतगति से पूर्ण करने हेतु आवश्यक उपाय करना।

(vi) निर्मित योजनाओं का संधारण –

अरपा नदी के जल ग्रहण क्षेत्र अन्तर्गत निर्मित सिंचाई योजनाओं, जल संवर्धन योजना पेयजल योजना का संधारण का कार्य।

(vii) वृक्षारोपण –

अरपा नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में वैज्ञानिक आधार पर वृक्षारोपण करना जिससे नदियों में जल संवर्धन हो सके।

7.5 प्राधिकरण के लिए बजट का प्रावधान –

जल संसाधन विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, नगरीय प्रशासन विभाग, वन विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा मांग संख्या-41 के अन्तर्गत प्राधिकरण के लिए बजट का प्रावधान किया जाएगा।

7.6 अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष कार्यालय के लिए राशि का प्रावधान –

प्राधिकरण के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं स्टाफ के लिए राशि का प्रावधान मांग संख्या 23/2701 राज्य आयोजना के अन्तर्गत किया जाएगा।

7.7 निधि से स्वीकृति जारी करना –

(i) शासन एवं प्राधिकरण से जारी प्रशासकीय स्वीकृति आदेश के लिए राशि संबंधित विभाग द्वारा जारी की जाएगी। कलेक्टर द्वारा जारी प्रशासकीय स्वीकृति आदेश के लिए संबंधित कलेक्टर द्वारा क्रियान्वयन विभाग को राशि उपलब्ध करायी जाएगी।

(ii) कार्य समाप्ति के उपरान्त पूर्णता प्रमाण पत्र क्रियान्वयन विभाग द्वारा प्राधिकरण को उचित माध्यम से निम्नानुसार उपलब्ध कराया जाएगा—

स. क्र.	प्रशासकीय स्वीकृति प्रदायक	पूर्णता प्रमाण पत्र जिसके माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा
1.	शासन अथवा प्राधिकरण	क्रियान्वयन विभाग के विभागाध्यक्ष
2.	कलेक्टर	संबंधित कलेक्टर

7.8 कार्य का निरीक्षण एवं प्रगति प्रतिवेदन –

प्राधिकरण के अन्तर्गत स्वीकृत कार्यों का निरीक्षण, क्रियान्वयन विभाग द्वारा विभागीय मापदण्डों के अनुसार किया जाएगा। क्रियान्वयन विभाग द्वारा प्रत्येक माह की 10 तारीख तक वित्तीय एवं भौतिक प्रगति निर्धारित प्रपत्र में प्राधिकरण एवं विभागाध्यक्ष को उचित माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा।

7.9. पर्यवेक्षण –

क्रियान्वयन विभाग द्वारा विभागीय मापदण्डों के अनुसार नियमित पर्यवेक्षण किया जाएगा।

7.10 लेखा संधारण –

क्रियान्वयन विभाग द्वारा विभागीय मापदण्डों के अनुसार लेखा का संधारण किया जाएगा।

7.11 प्राधिकरण की निधि से तैयार अस्तियों का रखरखाव एवं संधारण –

प्राधिकरण की निधि से निर्मित अस्तियों का लेखा-जोखा क्रियान्वयन विभाग द्वारा किया जाएगा। इन अस्तियों के उपयोग एवं रखरखाव का उत्तरदायित्व भी संबंधित विभाग का होगा। क्रियान्वयन विभाग इन अस्तियों को अपने रिकार्ड एवं बुक्स में लेंगे।

7.12 लेखाओं का पर्यवेक्षण, परीक्षण एवं अंकेक्षण –

- (i) लेखाओं का पर्यवेक्षण, परीक्षण एवं अंकेक्षण क्रियान्वयन विभाग द्वारा विभागीय मापदण्डों के अनुसार आंतरिक एवं बाह्य एजेन्सी से नियमानुसार कराना अनिवार्य होगा।
- (ii) जिला स्तर पर स्वीकृत कार्यों का आंतरिक एवं बाह्य एजेन्सी से पर्यवेक्षण, परीक्षण एवं अंकेक्षण करवाने का दायित्व संबंधित जिला कलेक्टर का होगा।
- (iii) वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात् प्राधिकरण के अन्तर्गत स्वीकृत कार्यों की सूचना, अध्यक्ष प्राधिकरण द्वारा अर्धशासकीय पत्र के माध्यम से प्राधिकरण के सदस्यों को सामाजिक अंकेक्षण के लिए दी जाएगी।

प्राधिकरण अन्तर्गत वेतन भत्ते, कार्यालय के फर्नीचर एवं दूरभाष, स्टेशनरी, पी.ओ.एल. आदि समस्त व्यय विभागीय बजट प्रावधान से किया जावेगा तथा मांग संख्या 23/2701, 0101 राज्य आयोजना (सामान्य), 3264—मण्डल स्थापना—01—001 के अन्तर्गत विकलनीय होगा।

8. प्राधिकरण के अध्यक्ष को सुविधाएँ :-

प्राधिकरण के अध्यक्ष के निजी कार्यालय के लिये स्टाफ की व्यवस्था राज्य शासन द्वारा निर्धारित सुविधाओं के अनुरूप होगी एवं इसकी पूर्ति जल संसाधन विभाग द्वारा विभागीय सैटअप से की जावेगी।

9. प्रकोष्ठ :-

प्राधिकरण के अन्तर्गत एक प्रकोष्ठ का गठन किया जावेगा, जिसमें कार्यालय के द्वितीय श्रेणी, राजपत्रित अधिकारी एवं अधीनस्थ कार्यालयीन स्टाफ होगा, जिसमें 01 सहायक अभियंता, 01 शीघ्रलेखक, 02 सहायक वर्ग-II/सहायक वर्ग-III एवं 02 भूत्य विभागीय सैटअप से होंगे।

प्राधिकरण का सैटअप परिशिष्ट—“ब” में संलग्न है।

10. मुख्यालय :-

अरपा बेसिन विकास प्राधिकरण का मुख्यालय बिलासपुर में होगा।

11. अरपा बेसिन विकास प्राधिकरण का गठन होने पर अरपा विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण का विघटन किया जाए।

हस्ता. /—

(डी.डी. सिंह)
सचिव,

परिशिष्ट—“अ”

प्रशासकीय स्वीकृति की अनुशंसा का प्रारूप

अरपा बेसिन विकास प्राधिकरण द्वारा निम्नलिखित कार्यों की प्रशासकीय स्वीकृति की अनुशंसा की जाती है –

स. क्र.	कार्य का नाम	कार्य अरपा नदी की जिस सहायक नदी/नाले के जलग्रहण क्षेत्र में स्थित है उसका नाम	गँव/ गँवों का नाम	विकासखण्ड	जिला	विधानसभा क्षेत्र	प्रस्तावित सिंचाई (हे. मे)	कार्य की लागत (रु.लाख में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

अध्यक्ष,
अरपा बेसिन विकास प्राधिकरण
बिलासपुर.

परिशिष्ट—“ब”

अरपा बेसिन विकास प्राधिकरण का सैटअप

स.क्र.	अधिकारी/ कर्मचारी	संख्या	विवरण
1	अध्यक्ष	1	—
2	उपाध्यक्ष	1	—
3	सदस्य	5	—
4	प्रथम श्रेणी राजपत्रित अधिकारी	1	—
5	द्वितीय श्रेणी	3	—
6	झापट्समेन	2	—
7	सहायक ग्रेड-1	1	—
8	स्टेनो	1	—
9	सहायक	3	अध्यक्ष-2, उपाध्यक्ष-1
10	स्टेनो टायपिस्ट	1	—
11	डाटा एण्ट्री आपरेटर	2	—
12	वाहन चालक	2	अध्यक्ष-1, उपाध्यक्ष-1